



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032025-261951
CG-DL-E-26032025-261951

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1362]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 25, 2025/ चैत्र 4, 1947

No. 1362]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 25, 2025/ CHAITRA 4, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

का.आ. 1380(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बारसे रोडोडेंडरोन अभयारण्य, सिक्किम के आसपास एक पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2172(अ) द्वारा, तारीख 27 अगस्त, 2014 को एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2172(अ) द्वारा, तारीख 27 अगस्त, 2014 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र,

असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2172(अ) द्वारा, तारीख 27 अगस्त, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्: -

“5. निगरानी समिति. – केंद्रीय सरकार उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

- | | |
|--|---------------------|
| (1) मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार | - अध्यक्ष, पदेन; |
| (2) मुख्य वन्य जीव वार्डन, सिक्किम सरकार | - सदस्य, पदेन; |
| (3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिक्किम सरकार | - सदस्य, पदेन; |
| (4) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (5) गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र सिक्किम से पारिस्थितिकी या पर्यावरण या वन्यजीव में एक विशेषज्ञ को तीन वर्ष की अवधि के लिए सिक्किम सरकार द्वारा नामित किया जाएगा। | - सदस्य; |
| (6) पर्यावरण या वन्य जीवन (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे सिक्किम सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा। | - सदस्य; |
| (7) ग्रामीण प्रबंधन और विकास विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि | - सदस्य, पदेन; |
| (8) कृषि विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| (9) शहरी विकास एवं आवास विभाग, सिक्किम सरकार का एक प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| (10) जिला कलेक्टर संबंधित | सदस्य, पदेन; |
| (11) प्रभागीय वनाधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी) | सदस्य, पदेन; |
| (12) मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) | - सदस्य सचिव, पदेन। |

(2) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में सम्मिलित हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आती हों, उसके पैरा 4 के अंतर्गत दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।

(3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में सम्मिलित नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।

(4) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या उप आयुक्त या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(5) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

- (6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को **उपाबंध-III** में निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।”

[फा. सं. 25/8/2013-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक “जी”

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 27 अगस्त, 2014 को अधिसूचना संख्या का.आ. 2172 (अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार तारीख 27 सितंबर, 2023 अधिसूचना संख्या का.आ. 4245 द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2025

S.O. 1380(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Barsey Rhododendron Sanctuary, Sikkim in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2172(E), dated the 27th August, 2014;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2172(E), dated the 27th August, 2014;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2172(E), dated the 27th August, 2014, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 the following paragraph shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee.** - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely:-

- | | | |
|-----|---|-------------------------------|
| (1) | Chief Secretary, Government of Sikkim | Chairman, <i>ex officio</i> ; |
| (2) | Chief Wild Life Warden, Government of Sikkim | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (3) | Principal Chief Conservator of Forests, Government of Sikkim | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (4) | One representative of the State Pollution Control Board | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (5) | One expert in ecology or environment or wildlife from Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment, Regional Centre Sikkim to be nominated by the Government of Sikkim for a period of three years | Member; |
| (6) | One representative of a Non-Governmental Organization working in the field of Environment or Wildlife | Member; |

- (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Sikkim for a period of three years
- | | | |
|------|---|--|
| (7) | One representative of Rural Management and Development Department, Government of Sikkim | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (8) | One representative of Agriculture Department, Government of Sikkim | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (9) | One representative of Urban Development and Housing Department, Government of Sikkim | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (10) | District Collector Concerned | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (11) | Divisional Forest Officer (In-charge of Protected Area) | Member, <i>ex officio</i> ; |
| (12) | Chief Conservator of Forest (Wild Life) | Member Secretary,
<i>ex officio</i> . |
- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-Sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in proforma specified in Annexure V.
- (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions”.

[F. No. 25/8/2013-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2172(E), dated the 27th August, 2014 and was last amended *vide* number S.O. 4245(E), dated the 27th September, 2023.